आकाशवाणी केन्द्र शिमला

21.12.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1800बजे

कैग रिपोर्ट

नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) ने प्रदेश में राजस्व प्राप्तियों व सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी की दर में अंतर होने पर सवाल खड़े किए हैं। धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र के आज अंतिम दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैग रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्व प्राप्तियों व जीएसडीपी की बढ़ौतरी की दर में भारी अंतर को पाटने की जरूरत है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2018–19 में प्रदेश के राजस्व प्राप्तियों 14 लाख 8 हज़ार 3 सौ 83 करोड़ रुपए के मुकाबले 2022–23 में बढ़कर 19 लाख 5 हज़ार 4 सौ 5 करोड़ रुपए हो गई। कैग ने रिपोर्ट में कहा कि जीएसडीपी में बढ़ोतरी की दर 7 दशमलव 2–6 फीसदी रही, लेकिन इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों में महज 2 दशमलव शून्य–9 फीसदी की बढ़ौतरी आंकी गई है। कैग ने राजस्व प्राप्तियों की बढ़ौतरी की दर में और सुधार की जरूरत जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022–23 में राज्य में राजस्व प्राप्तियां 38 हज़ार 89 करोड़ 50 लाख रुपए थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के खर्चों में वेतन, पेंशन व ब्याज के साथ–साथ उपदान पर होने वाला खर्च, कुल राजस्व खर्च 64 से 70 फीसदी है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार को राजस्व प्राप्तियों में ईजाफा करने में गैर आवश्यक उपदानों में कमी लाने के साथ–साथ सतत् आर्थिक विकास व राजकोषीय सेहत को बनाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही कैग ने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने से बचने की नसीहत भी सरकार को दी है।

एफआरबीएम

हिमाचल प्रदेश में बढ़ते राजस्व व राजकोषीय घाटे के साथ–साथ पेंशन व उपदानों पर होने वाले खर्च पर बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आज एफआरबीएम की रिपोर्ट सदन में पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में दिसंबर माह तक राजस्व घाटा बजट अनुमानों से एक हज़ार 4 सौ 93 करोड़ 25 लाख रुपए अधिक रहने का अनुमान है। राजस्व घाटा बढ़ने की वजह वेतन, पेंशन और उपदानों पर होने वाला अधिक खर्च है। एक हज़ार 4 सौ 93 करोड़ रुपए की बढ़ौतरी के साथ राजस्व घाटा बढ़कर 6 हज़ार 6 करोड़ 86 लाख तक पहुंचने का अनुमान एफआरबीएम में लगाया गया है। इसी तरह राजकोषीय घाटा 2 हज़ार 3 सौ 8 करोड़ 11 लाख रुपए की बढ़ोतरी के साथ 6 हज़ार 8 सौ 36 करोड़ 64 लाख

रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। बढ़ते खर्चों के साथ–साथ प्रदेश में राजस्व प्राप्तियों का अनुमान भी गड़बड़ाया है।

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार सिर्फ नीड बेस्ड नए संस्थान खोल रही है और भविष्य में भी इसी आधार पर संस्थान खोले जाएंगे। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में ये बात कही। इस दौरान उन्होंने अगले कुछ माह के दौरान प्रदेश में एसडीएम कार्यालयों का युक्तिकरण करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा कि ज़रूरत के आधार पर सरकार ने 37 संस्थान खोल दिए हैं, जबकि एक सौ 3 संस्थान खोलने की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इन संस्थानों के लिए नियुक्तियां की जा रही है। उन्होंने खुलासा किया कि मौजूदा सरकार ने सत्ता में आने के बाद कुल एक हज़ार 8 सौ 65 संस्थान बंद किए हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने कई ऐसे स्कूल खोल दिए, जहां एक भी विद्यार्थी नहीं था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने ऐसे संस्थानों का सर्वे करवाया और फिर बंद करने का निर्णय लिया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक हंसराज के प्रतिपूरक सवाल के जवाब में कहा कि चुराह विधानसभा क्षेत्र में बिजली का मंडल खोलने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा।

सत्र समाप्त

धर्मशाला के तपोवन में आयोजित प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र को आज अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। चार दिन तक चले इस सत्र में कुल एक सौ 88 तारांकित और 55 अतारांकित सवाल पूछे गए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि यह सत्र प्रदेश विधानसभा के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, क्योंकि इसी सत्र में और तपोवन परिसर से विधानसभा में शून्यकाल की शुरूआत हुई है।

नमस्कार।